

प्रमात खनल - 23-09-14

# अब जिले की हर पंचायत का बनेगा मास्टर प्लान : नीतीश

संवाददाता, पटना

## वार्ड स्तर पर बनेगी विकास योजना

पंचायतों के विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने नयी नीति तैयार की है. अब सूबे के सभी एक लाख 15 हजार 876 वार्डों द्वारा योजना बनायी जायेगी. वार्डों की योजनाओं का संग्रह पंचायत स्तर पर किया जायेगा. इसके आधार पर पंचायत का पांच वर्षों का मास्टर प्लान तैयार होगा. योजना बनाने के लिए हर वार्ड को साढ़े छह हजार रुपये दिये जायेंगे.

25 सितंबर से योजना बनाने का काम शुरू होगा और नवंबर तक इसे पूरा कर लिया जायेगा. सोमवार को 'हमारा गांव, हमारा विकास, इंटेसिव पार्टिसिपेट्री प्लानिंग एक्सरसाइज' पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में यह जानकारी डीडीसी, बीडीओ, कार्यक्रम पदाधिकारियों व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को दी गयी.

**293 प्रखंडों का चयन :** ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनंदिता अधिकारी ने मनरेगा के प्रावधानों में हुए बदलाव की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 60 फ्रीसदी योजनाएं कृषि से संबंधित होनी चाहिए. इस योजना को लागू करने के लिए बिहार के 293 प्रखंडों का चयन किया गया है. तीन दिनों तक वार्डों की योजनाओं को तैयार किया जायेगा. उसके बाद पंचायत और



कार्यशाला को संबोधित करते मंत्री नीतीश मिश्र.

ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया, एक पंचायत में औसतन 15 वार्ड होते हैं. हर वार्ड के लिए समान रूप से विकास योजनाओं का चयन नहीं होता है. इसलिए हर वार्ड की योजना तैयार करायी जा रही है. विभाग तीन-चार हजार करोड़ की योजनाएं तैयार करने में जुटा है. यह तभी संभव होगा, जब वार्ड स्तर पर वास्तविक योजनाएं तैयार की जाएं. दो-दो माह में योजनाएं तैयार की जायेंगी. इसी के आधार पर स्कीम की स्वीकृति दी जायेगी.

### गांवों की सूरत बदलें

विभाग के सचिव एसएम राजू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना है. सरकार की ओर से नयी पहल की गयी है. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार ने पदाधिकारियों को मोटिवेट करते हुए कहा कि आप योजना बनाते और उसे क्रियान्वित करते समय यह ध्यान रखें कि आप गांवों के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं. एक टीम लीडर की भूमिका अदा कर गांव की सूरत बदलनी है.

फिर प्रखंड स्तर पर ब्लॉक प्लानिंग टीम बनेगी.

ग्रामीण विकास के ओएसडी सतीश रंजन ने बताया कि पहली बार इसका प्रयोग नौबतपुर में किया जा चुका है.

अब इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जायेगा. यूएनडीपी के शुभेंद्र सान्याल ने बताया कि वार्ड की योजना निर्माण के समय सभी संसाधनों का लिखित डाटा तैयार किया जायेगा.